International Journal of
Global Multidisciplinary Research and Analytics

IJGMRA | ISSN (Online): 3107-6483
July-September 2025 | Vol. 01 | Issue 2

Website: www.thearyapublication.com

भारतीय उच्च शिक्षा का अन्तर्राष्ट्रीयकरण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की भूमिका

अजीत प्रताप*

शोधार्थी, आर0बी0एस0 कालेज, आगरा (उ0प्र0), भारत
ई-मेल: ajit.gupta82@gmail.com

DOI: **https://doi.org/10.5281/zenodo.17314228**
Accepted on: 20/09/2025 Published on: 10/10/2025

सारांश:

21वीं सदी के भारत में उच्च शिक्षा का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करना एक वैश्विक अनिवार्यता बनती जा रही है, जो कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में दूसरी पीढ़ी के सुधार की एक उपयोगी कुंजी प्रतीत हो रहा है। भारतीय शिक्षा प्रणाली में इस सुधार का इंतजार काफी लम्बे अरसे से किया जा रहा है, सन् 1990 के दशक में जब भारत ने आर्थिक उदारीकरण का एक क्रान्तिकारी कदम उठाया था तभी से ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की अपेक्षा की जा रही है किन्तु वर्तमान समय में जब से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया गया है तब से उच्च शिक्षा की दिशा एवं दशा पूर्णरुपेण परिमार्जित होकर अन्तर्राष्ट्रीयकरण की संभावना और अधिक प्रबल हुई है। इस सन्दर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में भी लक्ष्यित है कि भारत को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ''वैश्विक स्टडी डेस्टिनेशन'' बनाना है तथा इसी क्रम में एक महत्वकांक्षी रोड मैप भी तैयार करना प्रस्तावित है। एन0ई0पी0-2020 के मसौदे का प्रमुख उद्देश्य से एक वर्ष 2030 तक देश की उच्च शिक्षा का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करना है तथा विश्व की कुछ नामी-गिरामी यूनिवर्सिटियों (टाप 500 यूनिवर्सिटियों में से) को भारत में खोलने की इजाजत दी जायेगी। एन0ई0पी0-2020 की ही देन है कि यू0जी0सी0 ने भारत में विदेशी उच्च शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और संचालन विनियम-2023 की दिशा निर्देश जारी किया है। यू0जी0सी0 की यह पहल भारत ही नहीं वरन् वैश्विक स्तर पर एक नई सम्भावनों को जन्म दिया है जो भविष्य में एक मील का पत्थर साबित होगा और भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश और निरन्तर बढ़ती छात्र आबादी के अलावा विदेशी संस्थाओं में अध्ययन की असीम अभिलाषा लिए छात्र-छात्राओं को एक सुनहरे भविष्य के निर्माण में अपनी अहम भूमिका का निर्वाहन करेगी।

मुख्य शब्द :- उच्च शिक्षा, अन्तर्राष्ट्रीयकरण, एन0ई0पी0-2020, यू0जी0सी0, विदेशी युनिवर्सिटी।

प्रस्तावना:

अनादिकाल से प्रत्येक समाज व राष्ट्र अपने नागरिकों को शिक्षित-दीक्षित करके स्वयं को विवेकशील समाज बनाने की दिशा में सतत प्रयासरत रहा है। आधुनिक काल में ज्ञान, विज्ञान व कला कौशल के बदलते परिदृश्य में सम्पूर्ण विश्व तीव्रगति से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है तथा शिक्षा का क्षेत्र भी परिवर्तन की इस बयार से अछूता नहीं रहा है। यही कारण है कि प्रत्येक समाज व राष्ट्र देश, काल, परिस्थितियां के परिणामस्वरुप शिक्षा की बदलती आवश्यकताओं, व्यवस्थाओं एवं आकांक्षाओं को निरुप्रपित करने के लिए समय-समय पर अपने मूल्यों व लक्ष्यों पर आधारित शिक्षा-नीतियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से परिवर्तित एवं परिमार्जित करने का प्रयास किया जाता रहा है। लगभग 34 वर्षा की लम्बी अवधि के बाद आखिरकार 29 जुलाई 2020 को केन्द्रीय मंत्रीमण्डल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में 'नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020' सर्वसम्मति से स्वीकृत प्रदान करके राष्ट्र को एक ऐसी अनोखी एवं क्रांतिकारी शिक्षा नीति प्रदान की है जिससे विद्यालयी एवं उच्च शिक्षा में काया पलट करने वाले परिवर्तन लाने के मार्ग को प्रशस्त करने की आशान्वित कोशिश की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में विविध परिवर्तनों एवं सुधार के बावजूद अन्तर्मुखी अवस्था में घुट ही रही है। जबकि नई शिक्षा नीति-2020 नें इसे भौगोलिक सीमाओं से मुक्त करते हुए भारत को वैश्विक पटल पर ले जाने के लिए एक जीवन्त आधार तैयार करने का भगीरथ प्रयास किया है।

21वीं सदी के भारत में उच्च शिक्षा का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करना एक वैश्विक अनिवार्यता है, जो शैक्षिक गुणवत्ता, आर्थिक प्रतिस्पद्र्धा एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है। उच्च शिक्षा का अन्तर्राष्ट्रीयकरण भारतीय शिक्षा व्यवस्था में दूसरी पीढ़ी के सुधार की एक कुंजी के रुप में देखा जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 भारतीय छात्रों के साथ-साथ विदेशी छात्रों का भी ध्यानाकर्षित करके देश में विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना करके अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और क्रेडित हस्तांतरण प्रणाली को सक्षम बनाकर अन्तर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देकर भारत को वैश्विक शिक्षा केन्द्र के रुप में देखती है। ये उद्देश्य सन् 2030 तक सार्वभौमिक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के एन0ई0पी0-2020 के व्यापक नीतिगत व लक्ष्य के अनुरुप है। एन0ई0पी0-2020 के तमाम प्रस्तावों में से उच्च शिक्षा का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करना एक महत्वपूर्ण एवं दूरगामी प्रभावशाली सुझाव है। जो भारत को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 'वैश्विक स्टडी डेस्टिनेशन' बनाना और एक महत्वकांक्षी रोड मैप भी तैयार करने की दिशा में निरन्तर प्रयासरत

है। एन0ई0पी0-2020 के मसौदे को गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन से ज्ञात होता है कि विश्व की कुछ नामी-गिरामी विश्वविद्यालयों (विश्व के टाप 500 यूनिवर्सिटियों) में से कुछ को भारत में स्थापित व संचालित करने की इजाजत दी जाएगी और भारत में प्रवेश को सरल व सुगम बनाने के लिए आवश्यक कानूनी नियम-निर्देश बनाये जायेंगे तथा उन्हें देश के अन्य शैक्षणिक संस्थानों की तरह छूट भी दी जाएगी। हालही में शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार यू0जी0सी0 ने भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना और संचालन विनिमय-2023 लागू किया है। भारत सरकार एवं यू0जी0सी0 ने उच्च शिक्षा व्यवस्था को अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा के साथ एकीकृत करने तथा उसे विश्वस्तरीय बनाने की जो साहसिक पहल किया है, वह भारत को 'शैक्षिक विश्व गुरु' बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। शैक्षिक संस्थानों की संख्या की दृष्टि से भारत के पास दुनिया का सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा शिक्षा तंत्र है जहाँ लगभग 1200 से अधिक विश्वद्यािलय और 40,000 से अधिक महाविद्यालय हैं। किन्तु तकनीकी नवाचारों एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अभी बहुत पीछे है। इनमें से कोई भी 'क्यू0एस0 वल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग' में जगह नहीं बना सके, इसके अलावा 'ग्लोबल टेलंट' कांम्पिटिटिव इंडेक्स के 132 देशों की सूची में भारत का स्थान 72वें नम्बर पर था, जो भारत के उच्च शिक्षा तंत्र की बदहाली को दर्शाती है। भारत की विशाल जनसंख्या और लगातार बढ़ती छात्र दर आबादी के अलावा देशी-विदेशी शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन को असीम अभिलाषा के कारण वर्ष 2023-24 में लगभग 15 लाख छात्र-छात्राएं विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए गये तथा वर्ष 2024-25 में यह छात्र संख्या बढ़कर 18 लाख के करीब पहुंच गई है यू0जी0सी0 अन्तर्राष्ट्रीयकरण विनिमय 2023 के आधार पर भारत सरकार ने अब भारत में विदेशी विश्वद्यािलयों को अपना कैम्पस खोलने की स्वीकृत प्रदान कर दी है। जिसके फलस्वरुप ब्रिटेन के लिवरपूल यूनिवर्सिटी ने भारत के बेंगलूरु में अपना परिसर खोलने के लिए यू0जी0सी0 और शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं। भारत में अब तक पांच विदेशी यूनिवर्सिटियों ने जैसे-ब्रिटेन का साउथैम्पटन वि0वि0 गुरुग्राम में आस्टेलिया का डाकिन वि0वि0 व वोलोगोंग वि0वि0 गिफ्ट सिटी गुजरात में, तथा अमेरिका का इलिनांयस इंस्टिट्यूट आफ टेक्नोलाजी मुंबई में अपना-अपना परिसर खोल रहे हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि नई शिक्षा नीति-2020 एक ऐसी पहल है जो न केवल उच्च शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार के लिए लम्बा रास्ता तय करेगी वरन सरल व सहज शिक्षा तक सबकी पहंच एवं इसे वैश्विक स्तर पर प्रतस्पद्र्धी भी बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाहन करेगी।

भारत में उच्च शिक्षा के अन्तर्राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता:

भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था अपनी विशालता के मामले में विश्व के दूसरे नम्बर पर आती है। हमारे देश में लगभग 1200 विश्वविद्यालय तथा 40,000 के करीब महाविद्यालय संचालित हैं किन्तु इनमें से कोई भी विश्वविद्यालय व कालेज ऐसा नहीं है जो क्यू0एस0 वल्ड यूनिवर्सिट रैंकिंग 2025 में अपना कोई स्थान बना सका हो, भारत के युवा छात्रों में जैसे-जैसे तीव्रगति से तकनीकी इनोवेशिव व बेहतर गुणवत्ता परक उच्च शिक्षा की महत्वकांक्षा प्रबल हो रही है, वैसे-वैसे वे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विदेशों में विकल्प तलाशने के लिए मजबूर हो रहे हैं। भारत न तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कोई प्रगति कर पा रहा है और न ही योग्य काबिल छात्र-छात्राओं तथा शिक्षकों को अपनी ओर आकर्षित कर पा रहा है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में उच्च शिक्षा में लगातार नामांकन दर तेजी से वृद्धि हो रही है। इस समय लगभग 28 प्रतिशत छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा में दाखिला ले रहे। एन0ई0पी0-2020 के प्रस्तावित अनुमान के आधार पर वर्ष 2035 तक स्कूलों में दाखिला लेने वाले छात्रों में से 50 प्रतिशत छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए नामांकित करना लक्ष्यित है। जोकि अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। भारत में निरन्तर छात्रों की बढ़ती आबादी और विदेशी संस्थाओं में अध्ययन की महत्वकांक्षा व अभिलाषा ने वर्ष 2023-24 में लगभग 15 लाख छात्र-छात्राएं विदेशी शिक्षा के लिए देश से पलायन किये तथा वर्ष 2025 में यह संख्या बढ़कर 18 लाख तक जा पहुंची है। इस पलायन की वजह से भारत में जनशक्ति के साथ-साथ धन शक्ति का भी हराश हो रहा है अर्थशास्त्रियों का एक अनुमान है कि लगभग 40 मिलियन अमेरिकी डालर प्रत्येक वर्ष विदेशों में प्रवाहित हो रहा है जोकि भारत की कुल जी0डी0पी0 का लगभग 3 प्रतिशत है। साथ ही साथ मानव प्रतिभा का भी नुकसान हो रहा है। इन्हीं सब वजह से आज देश में उच्च शिक्षा का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता प्रबल हो गई है। समय-समय पर कई शिक्षाविदों ने भी इस बात पर भारत सरकार का ध्यानाकर्षित करने की कोशिश की है जिसकी वजह से आज भारत में उच्च शिक्षा के बाजार में दुनिया के श्रेष्ठ यूनिवर्सिटियों के कैम्पस को खोलने के लिए अपनी ओर ध्यानाकर्षित एवं प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयासरत है।

नई शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य:

किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास और आजीविकाओं को स्थायित्व देने में उच्च शिक्षा एक महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ है। 21वीं सदी की आवश्यकताओं को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का उद्देश्य अच्छे बहुमुखी

प्रतिभा, चिन्तनशील एवं सृजनात्मक छात्र-छात्राओं का विकास करना होता है। जिससे छात्रों को और अधिक सार्थक और सन्तोषजनक जीवन व कार्य भूमिकाओं के लिए निपुण बनाया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में भारतीय उच्च शिक्षा के अन्तर्राष्ट्रीयकरण के लिए अनेक उद्देश्यों की रुपरेखा को प्रमुख्य रुप से चार स्तम्भों में निरुपित किया गया है।

1. देशी-विदेशी छात्रों का ध्यानाकर्षित करना:

भारत के प्रतिभाशाली, काबिल एवं धनी छात्र अक्सर विदेश में पढ़ने के लिए चले जाते है। जहां वे उच्च गुणवत्ता वाली डिग्री हासिल करते हैं। वर्ष 2023-24 में करीब 15 लाख भारतीय छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा के लिए विदेश गये इसीलिय जब दुनिया के बड़े-बड़े विश्वविद्यालय भारत में अपने कैम्पस खोलेंगे तो विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों का एक बड़ा तबका उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा बहुत कम खर्च में ही अपने देश ही रहकर उन यूनिवर्सिटियों की डिग्रीयां हासिल कर सकेगा साथ ही भारत में विदेशी छात्रों के अध्ययन के लिए वर्ष 2024 में 50,000 छात्रों का नामांकित करने का भी लक्ष्य रखा गया था किन्तु यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सकाए किन्तु अब एक अनुमान के अनुसार यह माना गया कि वर्ष 2025 तक 60,000 अन्तर्राष्ट्रीय छात्र नामांकित हो सकते हैं।

2. दुनिया के नामी-गिरामी यूनिवर्सिटियों की कैम्पस स्थापित करना:

एन0ई0पी0-2020 के मसौदे में उच्च शिक्षा का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करना प्रस्तावित है। जिसकी वजह से यू0जी0सी0 ने भारत में विदेशी यूनिवर्सिटियों के परिसर की स्थापना एवं उनका संचालन विनिमय-2023 लागू किया है। जिसमें क्यू0एस0 वैश्विक यूनिवर्सिटी रैंकिंग के शीर्ष 500 में आने वाले विश्वविद्यालयों को अपने यहाँ उनके कैम्पस खोलने के लिए आमंत्रित कर रहा है। जिससे देश से बाहर पलायन करने वाले छात्रों की गतिशीलता कम होगी और प्रतिस्पद्र्धा को भी बढ़ावा मिलेगा।

3. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सांस्कृतिक हस्तानान्तरण:

नई शिक्षा नीति-2020 ने एक ऐसी पहल को जन्म दिया है जो न केवल उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की सम्भावनाओं के अवसर को उपलब्ध कराया है बल्कि उच्च शिक्षा तक सबकी पहुंच को भी सुनिश्चित करता है। यू0जी0सी0 भारतीय एवं विदेशी विश्वविद्यालयों के बीच अकादमिक सहयोग के लिए वैधानिक नियमों के निर्माण में प्रक्रियारत है ताकि हमारे देश के छात्रों को सीमा पार से संयुक्त और दोहरी डिग्रीयां प्राप्त करने की सुविधाएँ मिल

सके और छात्र-छात्राएँ आपस में एक दूसरे देशों की संस्कृति व सभ्यता से भी परिचित हो सकेंगे। इस तरह के अन्तर्राष्ट्रीय एकीकरण से भारतीय शिक्षा को वैश्विक स्तर पर ले जाने में मदद मिलेगी।

4. क्रेडिट ट्रांसफर व्यवस्था:

राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क भारतीय योग्यता व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को वैश्विक मानकों के साथ रेखांकित करके शैक्षणिक गतिशीलता की सुविधा के अवसर उपलब्ध करता है। जिससे छात्रों के साथ-साथ शिक्षकों एवं नीति नियामक निर्माणकर्ताओं को भी लाभांवित करेगी।

उच्च शिक्षा के अन्तर्राष्ट्रीयकरण में एन0ई0पी0-2020 की भूमिका:

वस्तुतः भारतीय ज्ञान परम्परा में समग्र एवं बहुविषयक अध्ययन एक प्राचीन पद्धति रही है। तक्षशिला व नालन्दा जैसी श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों से लेकर व्यापक भारतीय ज्ञान साहित्य में विभिन्न विषयों के संयोजन का विवरण मिलता है। इस विचार को भारतीय शिक्षा पद्धति में पुनः शामिल करना होगा क्योंकि यही 21वीं सदी की एक जरुरत है। आजादी के बाद भारत में उच्च शिक्षा पद्धति में विविध सुधारों के बावजूद अन्तर्मुख अवस्था में ही रही। इसीलिए देश को एक नई शिक्षा नीति बनाने की आवश्यकता महसूस हुई जिसे 34 वर्षों बाद पुनः एक नई राष्ट्र शिक्षा नीति-2020 का निर्माण किया गया जो भरत के सनातनी ज्ञान परम्परा के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा को अपने में आत्मसात किये हुए हैं। जो न केवल भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए तैयार है बल्कि वैश्विक शिक्षा जगत को भी एक नया आयाम देने की राह पर सतत प्रशस्त है। नई शिक्षा नीति-2020 भारतीय भाषाओ, योग, कला, संगीत, इतिहास, संस्कृति, आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति पर बल देता है, साथ ही नये-नये नवाचार की खोजों पर भी बल देता है। यह पहली ऐसी शिक्षा नीति है जो न केवल उच्च शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार के विविध आयाम खोजता है बल्कि समग्र व समावेशी शिक्षा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करता है तथा इसे वैश्विक स्तर पर भी प्रतिस्पद्र्धी भी बनाएगी। एन0ई0पी0-2020 में उच्च शिक्षा के अन्तर्राष्ट्रीयकरण का प्रावधान किया गया है, इसके तहत यू0जी0सी0ने भारत में विदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के कैम्पस की संचालन एवं स्थापना विनिमय 2023 का दिशा-निर्देश तैयार किया है। यही विनिमय विदेशी यूनिवर्सिटियों को प्रवेश प्रक्रिया, शिक्षकों की सेवा शर्ते, शुल्क संरचना को स्थापना के 10 वर्षों के बाद स्वदेश भेजने की स्वयत्ता प्रदान करते हैं और यह भी तय किया है कि ये यूनिवर्सिटी देश में संचालित अपने सभी कैम्पसों आनलाइन अथवा दूरस्थ शिक्षा के

बजाए आफलाइन माध्यम में पूर्ण कालिक कार्यक्रम व शिक्षा प्रदान करेंगे। भारत में विदेशी कैम्पसों से भारतीय छात्र-छात्राओं को सस्ती कीमतों पर सर्वसुलभ, गुणवत्तापूर्ण डिग्रीयां और कौशल मिलेंगे। इससे भारत में पढ़ाई के लिए एशिया एवं अफ्रीकी महाद्वीपों के छात्र भी आकर्षित होकर अध्ययन के लिए आयेंगे। विदेशी कैम्पसों के स्थापित हो जाने से विदेश में अध्ययन के लिए पलायन करने वाले छात्रों की संख्या में अंकुश लग सकेगा और साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और प्रतिभा पलायन को भी रोका जा सकेगा। ऐसे में भारत की वैश्विक शैक्षणिक साझेदारी में प्रागढ़ता आयेगी और यही शैक्षणिक साझेदारी भारत को एक नालेज इकोनामी बनाते हुए उसकी साफ्ट पावर को भी एक नई धार व दिशा देगी। इससे स्पष्ट होता है कि नई शिक्षा नीति-2020 भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था को बदलने और उसे वैश्विक स्तर पर बढ़ाने के लिए अहम भूमिका का निर्वाहन करेगी।

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को पांच वर्ष पूरे हो गए हैं। यह नीति अब पूरे देश में अपना संरचनात्मक आकार लेने लगी है। अकादमिक जगत के लोग भी इसको लेकर बहुत गम्भीर हो रहे हैं। यदि भारत को एक बार फिर वैश्विक शिक्षा केन्द्र (विश्वगुरु) बनाना है तो हमें वैश्विक अपेक्षाओं के साथ निरन्तर समन्वय स्थापित करना होगा। भारत में कभी नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे महान शिक्षा केन्द्र थे। आज देश में करीब एक हजार से अधिक विश्वविद्यालय या उसके समतुल्य शिक्षा केन्द्र हैं। जो निश्चित रुप से संतोष की बात है परन्तु अब जरुरत है कि भारत में दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों के साथ-साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और इसका अन्तर्राष्ट्रीयकरण एक सही दिशा की ओर बढ़ाया जाए। एन0ई0पी0-2020 का भारत उच्च शिक्षा का अन्तर्राष्ट्रीयकरण, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है। लेकिन प्रगति असमान बनी हुई प्रतीत होते हैं। भारत में विदेशी यूनिवर्सिटियों के कैम्पस स्थापना एवं संचालन एक स्वागत योग्य कदम है। अकादमिक व्यवस्था, कराधान, भूस्वामित्य और शिक्षकों की भर्ती आदि संबंधित नियामक तंत्र आदि सामान्य चिंता के विषय है। किन्तु सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि विदेशी संस्थाएं जो भारत में अपना कैम्पस संचालित करना चाहती है वे सहयोग और ज्ञान, कौशल के साझाकरण को बढ़ावा देने हेतु कार्य करें न कि सिर्फ व्यावसायिक एवं स्वार्थ हितों के लिए काम करने वाली शिक्षा की दुकानें बनकर रह जाएं। इन संस्थाओं में केवल अमीर वर्गों के लिए ही नहीं बल्कि वंचित वर्गों से आने वाले छात्रों के हितों को भी ध्यान में रखा जए ऐसा करके ही भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली का लक्ष्यित और

वास्तविक अन्तर्राष्ट्रीयकरण को सुनिश्चित किया जा सकता है और तभी नई शिक्षा नीति-2020 भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने और उसे वैश्विक स्तर पर बनाने के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकेगा।

सन्दर्भ:

- गुप्ता, ए. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: *एक साल परिचय*. शारदा पुस्तक भवन.
- गुप्ता, एस. पी. (2021). भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याए. शारदा पुस्तक भवन.
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (मसौदा), एमएचआरडी.
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020). 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति. *ई. मैगजीन, 2(20).*
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (2021). उच्च शिक्षा के अन्तर्राष्ट्रीयकरण के लिए दिशा निर्देश.
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (2023). भारतीय एवं विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच शैक्षणिक सहयोग.